उ.प्र. राज्य की प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एवं जबाबदेही एक अध्ययन

डॉ. तिर्मल सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग
श्री जे.एन.पी.जी. कालेज लखनऊ

जबाबदेही आज के युग की अति महत्वपूर्ण मॉग है क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद हम आत्म निर्भर होना तो दूर अपने कार्यो और उत्पादनों में गुणवत्ता तक स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी लगभग सभी उत्तम वस्तुओं के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यहॉ तक हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को भी दोयम दर्जे का मानने लगे हैं। मानवीय व्यवहार की ओर दृष्टि दौड़ायें तो चारो ओर अराजकता का वातावरण दिखाई पड़ता है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, निरक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण आदि तो समाज के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, भारतीय नागरिक स्वयं को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वर्गवाद, साम्प्रदायिकता एवं अन्ध विश्वास की कुप्रथाओं तक से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जनप्रतिनिधि हो, व्यूरोक्रेट या आम नागरिक कोई भी अपने कार्यो और उत्तरदायित्वों के लिए जवाबदेही नहीं लग रहा हैं।

आज शिक्षा का क्षेत्र भी सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। हमारे देश में विद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि हुई लेकिन गुणवत्ता में वॉछित सुधार नहीं कर पाये। शिक्षक और शिक्षार्थी तो हैं लेकिन शिक्षा नहीं। आज के इस प्रगतिशील एवं कठिन वैज्ञानिक स्पर्धा के युग में भी हमारे अधिकांश शिक्षक व शिक्षा दोनों पुराने घिसे पिटे ढर्रे पर चल रहे हैं, कैसे दूर होगी समाज एवं शिक्षा की ये बुराइयॉ, जबाबदेही की संकल्पना किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को हाथ में लेने तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा करने वाले से अपेक्षा करता है कि दिए गए कार्यो को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से पूरा करेगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाता हैं। कार्य पूरा हो जाने पर यदि उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो कार्य करने वालों को प्रशन्नता होती है, यदि कार्य अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो कार्य करने वाले को जबाब देना पड़ता है कि किन कारणों से एवं परिस्थितियों से विवश होकर वॉछित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। कार्य करने वाले का इस प्रकार देना ही जबाबदेही कहा जाता है।

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत जो उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित व्यक्तियों को सौंपा जाता है वह आधारिक रूप से सामाजिक महत्व का होता है। शिक्षा को राष्ट्रीय उन्नति और विकास से जोड़कर शिक्षक को राष्ट्र निर्माण के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य का उत्तदायित्व लेने के बाद यदि शिक्षा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती है तो इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को जबाब देना ही होगा और दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदारी न निभाने का परिणाम भुगतना होगा। शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों, सरकार, शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों एवं व्यवस्थापिका से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी और असफल होने पर उसके परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी होगी तभी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति गम्भीर हो सकेगा और वॉछित सफलता प्राप्त हो सकेगी।

1. शिक्षा में जबाबदेही के अध्ययन की आवश्यकता

जबाबदेही की समस्या बड़ी जटिल, कठिन तथा संवेदनशील है साथ ही साथ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जबाबदेही के बिना अराजकता की सम्भावना बनी रहती है। इसके अभाव में व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करने लगता है और अराजकता फैल जाती है। आज हम चारो ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जबाबदेही की बड़ी सीमा तक अवहेलना की जा रही है। जीवन का कोई भी क्षेत्र अथवा कार्य ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें पूर्णतः पारदर्शिता हो। जबाबदेही के अभाव के कारण भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, निष्क्रियता तथा अनुशासनहीनता का परिवेश है इस स्थिति पर शीघ्र से शीघ्र प्रगति पाना देश के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा में सम्बन्धित व्यक्तियों की जबाबदेही निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है।

1. कार्य समय से पूर्ण हो सके।
2. कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
3. प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ा है सक्रिय रहे।
4. कमजोर (आर्थिक रूप से) वर्गो को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
5. शिक्षार्थी को अपने अधिकार मिल सकें।
6. देश की विभिन्न क्षेत्रों में वॉछित एवं प्रतियोगितात्मक रूप से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो सके। इत्यादि।

2. शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालय

शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों के बारे में हम सब ने बहुत अच्छी तरह सुना हैं। शासकीय विद्यालय सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं तथा इसके विपरीत पब्लिक स्कूल धनी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं जिनमें समस्त व्यवस्थायें व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं। अब आइये आपको एक आइना सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विद्यालय में हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। जिसमें छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। छात्रों के अभिभावकों का सामाजिक स्तर, रहन–सहन एवं कितनी सुविधायें हैं इससे आप अछूते नहीं है। वहीं वे छात्र जिनके माता पिता का सामाजिक–आर्थिक स्तर कुछ ठीक है तो वे शहर में रहने को मजबूर हैं ताकि उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में अध्ययन कर सकें। एक गॉव का व्यक्ति शहर में रहकर बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु गॉव से पलायन करता है और उसको इसके बदले मिलता क्या है। उसे मिलता है एक ऐसा बेटा/बेटी जो ब्रान्डड कपड़े पहनने का शौकीन हो, पिता की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक थी फिर से वह वहीं पर आ चुका है जहॉ से चला था। अर्थात निम्न आर्थिक स्तर पर। यह सब क्यों और कैसे हुआ। पब्लिक स्कूल के मालिक जो पहले से ही धनी थे अब वे और धनी हो चुके है। जो गरीब विकसित हेाना चाहता था विकसित न हो सका और सम्पूर्ण जीवन एक सपना ही देखता रहा जो पूर्ण न हो सका। अब चर्चा करते हैं कि क्या सभी छात्र ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत हैं तो जबाब निश्चित रूप से ना में उत्तर आयेगा। क्योंकि पब्लिक स्कूल मे प्रवेश के मानक कुछ ऐसे हैं कि छात्र को हिन्दी, गणित, अंग्रेजी इत्यादि का प्रवेश कक्षा के स्तर से भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए और माता–पिता इतने शिक्षित होने चाहिए कि वे अपने वार्ड का ग्रह कार्य कराने और समझाने में सक्षम हों। आर्थिक स्थिति इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि वे उसकी यूनिफार्म से लेकर महॅगे–महॅगे खेल का सामान क्रय कर सकें। आज सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति देखकर भय लगता है कि हमारे देश की नई पौध जिसे फलता–फूलता देखना प्रत्येक मॉ बाप का सपना होता है। आज मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। एक परिदृश्य से भी अवगत कराता हूँ जिसमें पब्लिक स्कूल का शिक्षक जो मात्र अंग्रेजी बोलकर अभिभावकों को लुभाता है और उसके पास जीवन का वास्तविक अनुभव नहीं है। आज शिक्षक को ऐसे शिक्षण की आवश्यकता है जिसमें छात्र की पढाई जाने वाली विषय वस्तु उसके वास्तविक जीवन से ताल्लुक रखती हो। वहीं दूसरी ओर विडम्बना है कि शिक्षक तो अच्छी शैक्षिक योग्यता वाला भर्ती किया गया लेकिन उसे शिक्षण के अतिरिक्त इतने कार्यो में उलझा दिया गया कि कालान्तर में वही शिक्षा से कोसों दूर चला गया। चाहे जनगणना का कार्य हो, चुनाव का कार्य हो, राशन वितरण का कार्य हो, प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हो या राशन का रख रखाव इत्यादि ऐसे अनेकों अनगिनत कार्य हैं जिनमें अच्छे शिक्षक को उलझा दिया गया और दीर्धकालीन हानि समाज या फिर कहें देश को होना निश्चित हो गया। शिक्षा

प्रदान करने का कार्य अन्य सेवाओं से अलग है यदि शिक्षक शिक्षा प्रदान करने का निरन्तर कार्य करता रहेगा तो न केवल शिक्षक का विकास होगा बल्कि उसके छात्र भी विकसित होंगे जो बहुत जल्दी दिखाई तो नहीं देंगे लेकिन भविष्य में जब वो एक सुयोग्य नागरिक बनेगा तो निश्चित रूप से देश की सेवा में अपना योगदान देगा। आज न केवल जबाबदेही की जरूरत है बल्कि जरूरत है तो शिक्षक को पूर्ण सामाजिक सम्मान देने की। जब समस्त शिक्षकों को सामाजिक रूप से सम्मान हेतु कानूनी अधिकार होंगे और इन अधिकारों का ब्यूरोक्रेटस के द्वारा पालन कराया जायेगा और उनकी जबाबदेही तय की जायेगी तो निश्चित रूप से शिक्षक को कर्त्तव्य बोध होगा और वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण मनोयोग से निभायेगा।

पोषण तालिका–1

5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर क्रमांक	कम जन्मभार वाले शिशुओं का प्रतिशत (1990–97)	उन बच्चों का प्रतिशत (1990–97)			5 वर्ष से छोटे बच्चों का प्रतिशत (1990–97) जिनका				विटामिन ए पूरक खुराक प्रसार पर (6–59 माह) प्रतिशत 1998	आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 1992–98
		सिर्फ स्तरफर करते थे (0–3 माह)	स्तन पान के साथ पूरक आहार लेते थे (6–9 माह)	अब भी स्तनपा न करते हैं (20–23 माह)	बजन कम है सामान्य व गम्भीर	गम्भीर	शरीर दुबला है सामान्य न गंभीर	कद छोटा सामान्य व गंभीर		
49	**33**	**51**	**31**	**67**	**53**	**21**	**18**	**52**	**25**	**70**

शिक्षा तालिका–2

5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर क्रमांक	प्राथमिक स्कूल में भर्ती अनुपात 1990–97 सकल		कुल प्राथमिक स्कूल उपस्थिति प्रतिशत 1990–98		प्राथमिक स्कूल की 5वीं कक्षा तक पढ़ते बच्चों का प्रतिशत 1990–95
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
49	110	90	75	61	59

शोधकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें सरकारी एवं प्राइवेट) की स्थिति में सुधार हेतु कुछ ऐसे तथ्यों को सामने लाया जा सके जो बिगड़ती हुई प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित कुछ ऑकड़ों का विश्लेषण करने पर भारत में प्राथमिक शिक्षा एवं उनके बच्चों के पोषण की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि हम उनके प्रति कितने गंभीर है।

हमें जरूरत है बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य व शिक्षा की जिससे वह सुयोग्य नागरिक बन सकें। इसके लिए बच्चों के माता–पिता की जबाबदेही भी सुनिश्चित करने की जरूरत है यहॉ जेंडर भिन्नता भी एक समस्या है माता–पिता केवल और केवल पुत्र की चाह में जनसंख्या में अपनी आर्थिक स्थिति को अनदेखी करते हुए वृद्धि करते जाते हैं जिसका दुष्परिणाम न सिर्फ उस परिवार को बल्कि सम्पूर्ण समाज को भुगतना पड़ता है।

आइये आपको एक नजर उस बजट की ओर ले चलें जहॉ प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु बजट तो आवंटित होता आया लेकिन प्राथमिक शिक्षा में बदलाव न आया। और अब विगत वर्षो में बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था केन्द सरकार द्वारा करायी गयी जिसमें प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में रसोइयों द्वारा पका हुआ भोजन सभी छात्रों/छात्राओं को खिलाया जाता है जिसकी गुणवत्ता का अन्दाजा आप कभी स्वयं किसी प्राथमिक/जूनियर विद्यालय में भोजन करके आसानी से समझ सकते है। उधर छात्राओं/छात्रों के अभिभावक कुछ इस तरह बेफिक्र है कि अपनी जिम्मेदारी भूल पूर्णतः सरकार पर निर्भर होते चले जा रहे है परिणामतः जो गरीब है वह सरकारी निःशुल्क भोजन पर निर्भर होता चला गया और शिक्षा को अनुपयोगी मानने लगा वहीं जो आर्थिक रूप से मजबूत

है वह अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में अध्ययन हेतु प्रवेश दिलाने को मजबूर हुआ और पब्लिक स्कूल में प्रवेश कराने हेतु नगरों की तरफ पलायन हुआ। शिक्षा की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेंदार अधिकारी/समितियों के कारण सरकारी शिक्षा व्यवस्था के मनवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना हैं तब जिम्मेंदार अधिकारी/समितियों कों अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना पडेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. यूनिसेफ–2000, दुनिया के बच्चों की स्थिति।
2. शील, अवनीन्द्र शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, साहित्य रत्नालय कानपुर।
3. अग्रवाल, जे सीः शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
4. एन. सी. टी. इ. 1998, राष्ट्रीय करीकुलम फ्रेमवर्क 22.03.2010
5. गुप्ता, एस.पी. आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद–1991